rojgar with ankit

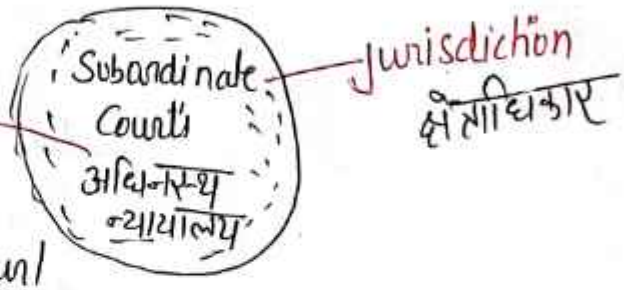
POLITY

पाँच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। यथा

(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
(2) परमादेश (Mandamus). → आदेश (Ordo) → देना।
(3) प्रतिषेध (Prohibition)
(4) उत्प्रेषण (Certiorari) तथा
(5) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

आदेश → सार्वजनिक अधिकारी, सरकार, निगम etc.
→ जब कोई इनमें से अपने कर्तव्यों (Duties) को करने से मना करता है, तब यह रिट Supreme / High Court द्वारा जारी की जाती है।

मना करना।
→ यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों (Senior Courts) Supreme / High Court द्वारा अधिनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) के विरुद्ध जारी की जाती है



ex. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा ⇒ S. Court / H. Court

उत्प्रेषण (Certiorari) ⇒ यह रिट Supreme / H. Court अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध (against) जारी की जाती है।

मंगवा लेना
→ जब कोई ऐसा मामला (matter) जिस पर सुनवाई (Hearing) का अधिकार Supreme / High Court को होता है

लेकिन वह मामला गलती से अधीनस्थ न्यायालय के पास चला जाता है तब यह रिट उस मामले को अपने पास मंगवाने के लिए जारी करते हैं।

Quo - warranto

अधिकार पृच्छा :- आपका क्या प्राधिकार है?
what is your Authority

⇓

यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद (Public office) के पद को अवैधानिक (illegal) तरीके से धारण करता है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व
[Directive Principles of State policy]

⇓ DPSP

⇓ आयरलैण्ड

Part (भाग) - IV

Art. (अनु०) ⇒ 36 - 51

⇒ भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था।

The aim of the Indian Constitution makers was to establish a welfare state in India.

कल्याणकारी राज्य ⇒ अर्थ ⇒ अधिक से अधिक लोगों का विकास।
Welfare State

⇓ DPSP

Art. 36 ⇒ राज्य की परिभाषा (Defination of State)

⇓ (Art. 12 के समान)

rojgar with ankit

अनुच्छेद - 37 में कहा गया है कि "इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू (En-Forced) नहीं कराया जा सकता है,
विधि निर्माण में इन तत्वों का (DPSP) प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।

Article-37 States that "The provisions of this part Cannot be enforced by any Court; it shall be the duty of the State to use these elements in law-making."

J.R ⇒ उल्लंघन / Voilation ⇒ Art. 32 ⇒ S.Court, Art. 226 ⇒ H.Court
↳ के न्यायालय द्वारा लागू (execute by the Court)

J.R ⇒ राज्य के विरुद्ध
↳ Art. 12, Art. 36

DPSP ⇒ राज्य के लिए निर्देश (Direction for State)
या सरकारें

⇒ सरकार - नीति (Policy) निर्माण - ex. ⇒ उज्ज्वला योजना
⇒ वृद्धा पेंशन योजना
⇒ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

रोजगार का अधिकार → मनरेगा

अनुच्छेद 38 (1) - राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके.

Article 38 (1) - Directs the State to promote public welfare and Strive to establish a Social order in which Social, economic and political justice is assured to every Individual

Art. 38 ⇒ लोक कल्याण (Public welfare) ⇒ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक → न्याय Justice

राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा, अनु. 39 (घ)
The State Shall provide equal pay for equal work to every Citizen, whether male or female, Article 39 (d)

Lm. Imp

⇒ सरकारी नौकरी ⇒ वेतन (Salary)
⇒ मजदूरी (Wage) ⇒ समान ⇒ male (A), female (B) → Govt. Teacher ⇓ Salary = समान

अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठायेगा
Article 40 provides that the State Shall take Steps to Constitute Gram panchayats.

Art. 40 ⇒ पंचायतों का गठन

→ 73 CA 1992 ⇒ पंचायतों को संवैधानिक
↳ त्रिस्तरीय (Three tier Panchayat's)
ग्राम स्तर
प्रखण्ड (Block)
जिला स्तर

rojgar with ankit

अनुच्छेद - 41 - सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें।
वृद्धा पेंशन योजना — सरकारी अस्पताल

Article 41 - All citizens have the right to employment and education according to their abilities and to receive public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disability.

नागरिक (citizen) ⇒ योग्यता (Qualification) ⇒ नौकरी (job)
↳ शिक्षा (education)